Nai Dunia (Indore), 28th December 2021, Page-5

शोध-शिक्षण को समन्वय से मिली गति

आइआइटी इंदौर ● संस्थान ने 38 राष्ट्रीय और 38 अंतरराष्ट्रीय समझौते किए

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। आइआइटी इंदौर अपने साथ कई संस्थानों को जोड़ता जा रहा है। अब तक आइआइटी 38 राष्ट्रीय और 38 अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से समझौता कर चुका है। इसमें 2021 में 12 राष्ट्रीय समझौते शामिल हैं। इसमें मध्यप्रदेश के भी कई संस्थानों के नाम शामिल हैं।

आइआइटी इंदौर स्थानीय संस्थानों के साथ भी शोध और शिक्षण कार्यों को बढ़ाना चाहता है। इसमें भारतीय प्रबंध संस्थान (आइआइएम) इंदौर, मिलिट्री कालेज आफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (एमसीटीई), इंदौर नगर निगम और अन्य संस्थान सम्मिलित हैं। हाल ही में आइआइटी इंदौर ने शासकीय और निजी कालेजों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित करना शुरू कर दिया है। जिन शिक्षण संस्थानों में शोध के साधन नहीं हैं या कोई प्रोफेसर या शोधकर्ता नए विषयों पर शोध करना चाहता है तो उन्हें भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यवाहक निदेशक प्रो. नीलेश कुमार जैन का कहना है कि उच्च संस्थानों की खुद के साथ समाज के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। इसी के तहत हम स्थानीय प्रशासन, शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के साथ तालमेल बढ़ा रहे हैं।

12 संस्थानों से समझौते

आइआइटी इंदौर अब तक 38 राष्ट्रीय और 38 अंतरराष्ट्रीय समझौते कर चुका है। 2021 में 12 संस्थानों से समझौते हुए हैं। इसमें आइआइएम इंदौर, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल, उज्जैन नगर निगम, इंदौर नगर निगम, देवास नगर निगम, मध्यप्रदेश काउंसिल आफ साइंस एंड टेक्नोलाजी, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट आफ गुड गवर्नेंस एंड पालिसी एनालिसिस, भारतीय जल सेना, एमसीटीई महू और अन्य संस्थान शामिल हैं।

दो साल से एमबीए (दूरस्थ शिक्षा) में प्रवेश नहीं, कार्यपरिषद सदस्य ने मांगा हिसाब

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय

- आफलाइन कोर्स के लिए विभाग के पास एक भी शिक्षक नहीं
- पत्र लिखकर पांच बिंदुओं पर दस साल की जानकारी मांगी

इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सबसे कमाऊ विभाग कहे जाने वाले दूरस्थ शिक्षा निदेशालय से संचालित एमबीए (दूरस्थ शिक्षा) कोर्स में इस साल भी कोई प्रवेश नहीं हुआ है। लगातार दूसरा सत्र कोर्स के लिए जीरो ईयर घोषित हो चुका है, क्योंकि आफलाइन कोर्स के लिए विभाग के पास एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। इससे विभाग की आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब कार्यपरिषद सदस्य डा. मंगल मिश्र ने कोर्स से जुड़ी जानकारी मांगी है। इसमें बीते दस साल का हिसाब देना होगा। विभाग को आनलाइन एमबीए (दूरस्थ शिक्षा) चलाने की अनुमति मिली है।

कार्यपरिषद सदस्य डा. मिश्र ने सोमवार को विश्वविद्यालय को एक पत्र लिखा है। इसमें निदेशालय से एमबीए कोर्स के बारे में पूछा है। इसमें 2010-11 से लेकर 2021-22 तक पांच बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। इसमें बीते दस साल में विभाग में निदेशक सहित एमबीए (दूरस्थ शिक्षा) में विद्यार्थियों की संख्या, प्रवेश और परीक्षा शुल्क, कुल व्यय और बचत का हिसाब शामिल है। डा. मिश्र ने कहा कि प्रबंधन विषय में एमबीए कोर्स के कारण निदेशालय पहले आइएमएस की इमारत में संचालित होता था, लेकिन अब इंजीनियरिंग विभाग में चलाया जा रहा है। विभाग का स्थान बदला है। इससे विद्यार्थियों को खासी परेशानी हो रही है। इस बारे में कार्यपरिषद सदस्यों से पूछा नहीं गया। प्रभारी कुलसचिव अनिल शर्मा का कहना है कि कार्यपरिषद सदस्य का पत्र मिला है। विवि अगले कुछ दिनों में सारी जानकारी उन्हें उपलब्ध करवा देगा।

सवा साल पहले मिली स्वीकृति

उच्च शिक्षा अनुदान आयोग ने 2019 में दूरस्थ शिक्षा में बदलाव को लेकर आवेदन बुलाए थे। निदेशालय ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है और प्रस्ताव बनाकर भेजा। जून 2020 में मात्र आनलाइन एमबीए को मंजूरी मिली है। अब कोर्स संचालन करने के लिए निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। बीस हजार सीटों पर प्रवेश के लिए एजेंसी की तलाश चल रही है। वित्त और तकनीकी निविदा कई एजेंसियों ने भेज रखी है। सूत्रों के अनुसार ठेके पर एमबीए कोर्स को देने को लेकर कार्यपरिषद सदस्यों में काफी नाराजगी है।

कालेजों की नैक ग्रेड सुधारने बनाया सेल

इंदौर। कालेजों को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) से अच्छी ग्रेड मिल सके, इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग अब आगे आया है। विभाग ने स्टेट लेवल नैक सेल (एसएलएनसी) बनाया है, जो सेल्फ स्टडी रिपोर्ट (एसएसआर) बनाने में मदद करेगा। कालेजों को रिपोर्ट तैयार करने से पहले सेल से मार्गदर्शन या परामर्श लेना होगा। उसके बाद ही रिपोर्ट नैक के सामने प्रस्तुत की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, नैक निरीक्षण करवाना शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनिवार्य है। कई कालेज पहली बार आवेदन कर रहे हैं। उन्हें 130 बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करने में दिक्कतें आ रही हैं। दरअसल, सेल बनाने के पीछे विभाग ने इसलिए कदम उठाया है, क्योंकि कुछ कालेजों ने इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल (आइक्यूएसी) से बिना सलाह रिपोर्ट भेजी। इसके चलते कालेजों को सी ग्रेड से संतुष्टि करनी पड़ी। बाकी कालेजों को अच्छी ग्रेड मिले, इसके लिए सेल बनाया है। यूजीसी ने 2022 तक प्रत्येक सरकारी और निजी कालेज को नैक निरीक्षण करवाने के निर्देश दिए हैं। 70 प्रतिशत कालेज पहली मर्तबा नैक के लिए आवेदन कर रहे हैं। विभाग ने सेल की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी डा. उषा नायर को दी है। अधिकारियों के मुताबिक सेल को पहले एसएसआर भेजना है। यहां से अनुमति मिलने के बाद कालेजों को आइआइक्यूए के लिए जानकारी दर्ज करनी है। अतिरिक्त संचालक डा. सुरेश सिलावट ने बताया कि कालेजों को सेल के बारे में जानकारी भेज दी है।